



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2001/27 अग्रहायण, 1923

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 18 दिसम्बर, 2001

संख्या 1-75/2001-वि०स०.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2001

3600

असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 18 दिसम्बर, 2001/27 अग्रहायण, 1923

(2001 का विधेयक संख्यांक 18) जो आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर.स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन अधिनियम, 1999 (2000 का 19) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन संक्षिप्त नाम (संशोधन) अधिनियम, 2001 है।

(2000 का 19) 2. हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके बृहत नाम पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत नाम में "लोक निक्षेप विनियमन" शब्दों के स्थान पर, "निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) संरक्षण" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (1) में, "लोक निक्षेप विनियमन" शब्दों के स्थान पर, "निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 1 का संशोधन।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने, राज्य में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के क्रिया-कलापों का नियन्त्रण करने और इन कम्पनियों में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन विधेयक, 1999 पारित किया था। विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भारत सरकार को भेजा गया था। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, विचार व्यक्त किया कि कानून का संक्षिप्त नाम उपदर्शित करता है कि कानून, लोक निक्षेप का विनियमन करने का आशय करता है जो, विधेयक की स्कीम के विषय और उद्देश्य को परावर्तित नहीं करता है। इन टीका टिप्पणियों का उत्तर देते समय, राज्य सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देने के पश्चात्, संक्षिप्त नाम उचित रूप से संशोधित किया जायेगा। राष्ट्रपति द्वारा उपर्युक्त विधेयक को 29-7-2000 को अनुमति दी गई और यह हिमाचल प्रदेश लोक निक्षेप विनियमन अधिनियम, 1999 (2000 का 19) बना। भारत सरकार को दिए गए आश्वासन को पूर्ण करने के लिए, पूर्वोत्तर अधिनियम के नाम को प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है। अतः पूर्वोत्तर अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख 2001.

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 18 of 2001.

**THE HIMACHAL PRADESH REGULATION OF DEPOSITS
(AMENDMENT) BILL, 2001**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*to amend the Himachal Pradesh Regulation of Deposits Act, 1999
(Act No. 19 of 2000).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Regulation of Deposits (Amendment) Act, 2001. Short title.

2. In long title of the Himachal Pradesh Regulation of Deposits Act, 1999 (hereinafter referred as the "principal Act"), for the words "REGULATION OF PUBLIC DEPOSITS", the words and brackets "PROTECTION OF INTERESTS OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS)" shall be substituted. Amendment of long title.

3. In section 1 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Regulation of Deposits", the words and brackets "Protection of Interests of Depositors (in Financial Establishments)" shall be substituted. Amendment of section 1.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To control the activities of Non-Banking Financial Companies in the State and to protect the interests of the depositors in these companies, the Legislative Assembly had passed the Himachal Pradesh Regulation of Public Deposits Bill, 1999. The Bill was sent to the Government of India for the assent of President. The Government of India, Ministry of Finance has made observations that the short title of the statute indicates that the statute intends to regulate the public deposits, which does not reflect the subject and objects of the scheme of the statute. While replying these observations, it was assured by the State Government that after the Bill is assented to by the President, the short title shall be suitably amended.

The said Bill was assented to by the President on 29-7-2000 and it became the Himachal Pradesh Regulation of Deposits Act, 1999 (Act No. 19 of 2000). In order to fulfil the assurance given to the Government of India, it has become necessary to substitute the title of the Act *ibid*. Thus, this has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:

The....., 2001.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-